

desirability of adopting a standard practice of specifying a single rate at which private investors are asked to sell power. The Committee felt that adoption of a simple tariff system would also eliminate the need of offering guaranteed PLF linked return on equity.

(c) and (d) Setting up of private power projects normally comes under the realm of the State Governments. However, the Control Electricity Authority scrutinises the costs and tariffs of these projects and accords techno-economic clearance only when it is satisfied that the cost are reasonable.

बैंकों की रुण्ण उद्योगों में फंसी राशि

59. श्रीपती सुवर्णा स्वराज़:

श्री राम जेठपलानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की बहुत बड़ी राशि देश के रुण्ण उद्योगों में फंसी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऐसी कितनी-कितनी राशि अनुत्पादक कर्त्त्वों में फंसी हुई थी; और

(ग) अनुत्पादक क्षेत्र में फंसी हुई ऐसी राशि उपरोक्त वर्ष के दौरान उद्योग के विस्तार एवं विकास के प्रयोजनार्थ बैंकों द्वारा दी गई कुल राशि का कितना-कितना प्रतिशत थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवी प्रसाद पाल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त हुए छमाही आंकड़ों के आधार पर, देश में रुण्ण/कमज़ोर औद्योगिक इकाइयों पर बकाया राशि और मार्च 1992, मार्च 1993 और मार्च 1994 (अधिन उपलब्ध) के अन्त की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग को कुल बकाया बैंक

रुण्ण की तुलना में ऐसे बकाया की प्रतिशतता, निम्नप्रकार थी:

(करोड़ रुपए)

के अन्त की बकाया राशि	उद्योग को कुल बैंक स्थिति	बैंक राशि की तुलना में बकाया राशि की प्रतिशतता
मार्च, 1992	11533.30	17.6
मार्च, 1993	13134.44	16.7
मार्च, 1994	13695.74	17.0

काले धन की मात्रा में निरन्तर बढ़ि होना

60. श्री सत्य प्रकाश मालवीयः

श्री अनन्तराम जायसवालः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में काले धन की मात्रा हजारों करोड़ रुपये में है और यह राशि निरन्तर बढ़ती है;

(ख) यदि हाँ, तो काले धन की यह राशि कुल कितनी है और काले धन की उक्त राशि की मात्रा में ज्यादातर राशि किस घंथे से पैदा होती है; और

(ग) क्या सरकार ने देश में तीव्र गति से बढ़ रहे काले धन की मात्रा पर अंकुश/रोक लगाने हेतु कोई ओस कारबाई की है; यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कारबाई की गई है और उसका क्या परिणाम रहा है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. बन्द्रजोखर मूर्ति): (क) और (ख) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा 1983-84 में किए गए अध्ययन में 31584 करोड़ ₹ से 36786 करोड़ ₹ के बीच काले धन का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद इस विषय पर कोई प्रमाणिक अध्ययन नहीं किया गया है और अतः काले धन की मात्रा को बताना अथवा सर्वाधिक काले धन को पैदा करने वाले कारोबारों का पता लगाना संभव नहीं है।

(ग) जी, हाँ। सरकार काले धन की बढ़ि को ऐकने के लिए समय-समय पर जैसा भी आवश्यक समझा जाए, आवश्यक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती आ रही है। कराधान की दरों को